उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

सच का साथी..

बी पी एस न्यूज

www.bpsnews.in

(वर्ष-9 अंक-6)

पृष्ठ 8 मूल्य 2/रुपया

सोमवार 11 मार्च, 2024

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024
आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान अवश्य करें

अब सैफई के नाम से डर नहीं लगता: सीएम 6

पत्रकार व उनके परिवार का कराया गया निशुल्क स्वास्थ्य 8

आजमगढ़ में सपा पर जमकर बरसे पीएम मोदी.

परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो भी ढहे

नए एयरपोर्ट टर्मिनल समेत कई हजार करोड़ रूपए की परियोजनाओं का पीएम ने किया शुभारम्भ

आजमगढ़ से कई जिलों के एयरपोर्ट का किया उद्घाटन

पीएम मोदी पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आज़मगढ़, चित्रकूट, मोरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर एयरपोर्ट के 12 नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों के तीन नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री लखनऊ और रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ 2,000 से ज्यादा किफायती फ्लैट बनाए गए हैं। पीएम रामपुर-रुद्रपुर के पश्चिमी हिस्से के चार लेन मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे. वह प्रयागराज, जौनपुर और इटावा में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे।

आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आज़मगढ़ पहुंच कर सपा पर खूब बरसे। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम ने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। वहीं, 5 शहरों के हवाई अड्डों का लोकार्पण किया। यहां पीएम मोदी 42,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज़मगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देशभर में 9,800 करोड़ रुपये से अधिक की 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया।

पीएम मोदी ने सौगातें देने के बाद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आदरणीय मंत्री,अन्य महानुभाव और आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई और बहनों का अभिनंदन करता हूं। मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग-अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं। आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछले इलाकों में गिनते थे। आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34000 करोड रुपए के प्रोजेक्ट इसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आजमगढ़ के साथ-साथ श्रावस्ती मुरादाबाद चित्रकूट अलीगढ़ जबलपुर ग्वालियर लखनऊ पुणे कोल्हापुर दिल्ली और आदमपुर इतने सारे एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से कम हुआ है। इसका एक उदाहरण ग्वालियर का एयरपोर्ट भी है यह एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया। मोदी ने कहा कि आज यह तीन हवाई अड्डा पर नए टर्मिनल भावनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। यह सारे प्रयास देश के सामान्य मानवीय के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा शहर और सुलभ बनाएंगे।

जातिवाद, परिवार और वोट बैंक के भरोसे बैठे इडिंया गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। वहां चलने जातिवाद और पुष्टिकरण की राजनीति विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है ।यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंत के खतरों को भी देखा है और यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद , चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं।

कांग्रेस इलेक्शन कमिटी की बैठक, 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल

लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। राजनीतिक दल किस उम्मीदवार को कौन सी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए, उसके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में यूपी के 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने यूपी में अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा नहीं की है। वहीं, इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल सपा ने यूपी के कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का एलान कर दिया है।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। गठबंधन के तहत यूपी में कांग्रेस को 17 सीटे मिलेगी, बाकी सीटे सपा और गठबंधन के अन्य साथी के खाती में गई हैं। सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं, कांग्रेस यूपी के 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है।

संपादकीय

किसान और सरकारें

उल्लेखनीय है कि पंजाब–हरियाणा सीमा पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर गत तेरह फरवरी से किसान आंदोलनरत हैं। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं व बच्चों की भी भागीदारी रही है। गत इक्कीस फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर टकराव के दौरान बठिंडा के युवक शुभकरण की मौत हो गई थी। अब अदालत ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट ने आंदोलन के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए शुभकरण की मौत के मामले में जांच के लिये एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश समेत तीन सदस्यीय कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है। कमेटी में हरियाणा व पंजाब के एडीजीपी भी शामिल होंगे। हालांकि, अदालत में भी इस मुद्दे को लेकर हरियाणा व पंजाब सरकारों की दलीलें सामने आती रही हैं। एक ओर हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि कि पंजाब सरकार ने शुभकरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। जिस पर कोर्ट का कहना था कि इस रिपोर्ट को देने में इतने विलंब की तार्किकता क्या है। बहरहाल, अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद किसान आंदोलनकारियों व सरकारों को अपनी रीति–नीतियों पर मंथन करना चाहिए। निस्संदेह, अदालती टिप्पणियां विचारणीय हैं कि जिन किशोरों को स्कूल में होना चाहिए, वे हथियारों के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? यह भी कि बॉर्डर पर किसानों व सरकार के बीच टकराव के चलते युद्ध जैसे हालात क्यों हैं? अदालत ने हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध चित्रों के आधार पर कहा कि लोग तलवार व तेजधार हथियारों के साथ देखे जा रहे हैं, क्या यह लोकतांत्रिक आंदोलन है? वहीं दूसरी ओर अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि खनौरी भारत–पाक की सरहद नहीं थी तो फिर किसानों पर गोलियां क्यों चलायी गई? साथ ही गोलियों और छर्रों के इस्तेमाल का विवरण मांगा। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि हिंसक प्रतिरोध में बीस से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई बार चेतावनी के बाद पहले लाठीचार्ज, फिर आंसू गैस तथा बाद में वॉटर कैनन का प्रयोग किया गया। स्थिति न सुधरने के बाद रबड़ की गोलियां चलायी गई थीं। उम्मीद है, दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालेंगे।पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने हालिया किसान आंदोलन के तौर–तरीकों व सरकारों की कारगुजारियों को लेकर जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, वे आंख खोलने वाली हैं। हरियाणा–पंजाब की सीमा पर विगत तीन सप्ताह से मोर्चा संभाले किसान आंदोलनकारियों के तौर–तरीके व उससे निपटने के सरकारों द्वारा उठाये गए कदम मर्यादित व्यवहार पर नये विमर्श की जरूरत बताते हैं। यह सर्वविदित है कि किसानों की दिल्ली कूच की कोशिशों और पुलिस प्रशासन की उन्हें रोकने के प्रयास में लगातार टकराव है।

पेड़ों के बिना बेमानी वन्यजीव संरक्षण का दावा

इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि यह संकट कुछेक वन्य जीवों का ही सवाल नहीं है, बल्कि दूसरी प्रजातियों के अस्तित्व से भी जुड़ा है। उस दशा में उन दूसरी प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकीय संतुलन का बिगाड़ अवश्यंभावी है।बीते कुछ महीनों से जंगलों और पेड़ों की अवैध कटाई का मसला विशेष रूप से चर्चा में है। इस मसले पर देश की सुप्रीम अदालत काफी गंभीर है और उसने संज्ञान लेना शुरू भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट रिजर्व नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार के पूर्व वन मंत्री और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी की खिंचाई की व फटकार लगाई।

सरकार देश में राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में बढ़ोतरी का दावा करते नहीं थकती। एक समय विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके बाघों की तादाद में बढ़ोतरी वास्तव में प्रशंसा का विषय तो है ही, गर्व का विषय भी है। हाल ही में जारी केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट में तेंदुओं की तादाद में बढ़ोतरी का दावा किया गया है, और कहा गया है कि यह देश में जैव विविधता के प्रति भारत के अटूट समर्पण का प्रमाण भी है। अब तेंदुओं की संख्या बढ़कर करीब 13,874 हो गयी है। सरकार की उस घोषणा का भी स्वागत किया जाना चाहिए जिसके तहत सरकार ने वन्यजीवों की सात प्रजातियों यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीते के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बनाया है। इसकी सफलता उसी दशा में संभव है जब देश–दुनिया में वन्य जीवों के लिए न केवल उनके अनुकूल वातावरण हो, और साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यहां इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि वन्य जीव और वन्य जीवन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है।जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी, अनियंत्रित औद्योगिक विकास और शहरीकरण के कारण जहां जंगलों की बेतहाशा कटाई के चलते वन्यजीवों के आवास लगातार खत्म किये जा रहे हैं, वहीं वन्य जीवों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। यही अहम कारण हैं कि वन्यजीव भोजन की तलाश में अब मानव बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। इसका दुष्परिणाम वन्यजीव–मानव संघर्ष के रूप में सामने आया है। इस संघर्ष को टालने का एकमात्र समाधान है जंगलों की कटाई पर रोक लगाना। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि यह संकट कुछेक वन्य जीवों का ही सवाल नहीं है, बल्कि दूसरी प्रजातियों के अस्तित्व से भी जुड़ा है। उस दशा में उन दूसरी प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकीय संतुलन का बिगाड़ अवश्यंभावी है।बीते कुछ महीनों से जंगलों और पेड़ों की अवैध कटाई का मसला विशेष रूप से चर्चा में है। इस मसले पर देश की सुप्रीम अदालत काफी गंभीर है और उसने संज्ञान लेना शुरू भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट रिजर्व नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार के पूर्व वन मंत्री और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी की खिंचाई की व फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई इस प्रकरण की पहले ही जो जांच कर रही है, वह तीन महीने में इसकी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करे। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को भविष्य में ऐसे कारनामें रोके व पहले हो चुके नुकसान की भरपायी के लिए तत्काल कदम उठाए।दरअसल पेड़ों की कटाई जैसे मसले पर देश की सुप्रीम अदालत की यह टिप्पणी एक सबक है। उसने कहा है कि वैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखने जैसे पूर्व वन मंत्री और वन अधिकारी के दुस्साहस आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यह विडंबना है कि वन अधिकारी पर गंभीर आरोप होने के बावजूद तत्कालीन वन मंत्री ने नियमों की अनदेखी कर उन्हें डीएफओ नियुक्त कर दिया। यह पूरा मामला राजनेता, नौकरशाहों की मिलीभगत का ज्वलंत उदाहरण है।गौरतलब है कि कोर्ट की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पहले सीटीआर के कालागढ़ वन प्रभाग के पाखरो और मोरघट्टी वन क्षेत्रों में 2021 में बाघ सफारी के संबंध में निर्माण सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों के लिए पूर्व मंत्री और वनाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल, यह मामला अधिवक्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका के चलते उजागर हुआ जिसमें पाखरो टाइगर सफारी में अवैध निर्माण के साथ–साथ अवैध रूप से हजारों पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया था। पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर देश में यह पहला मामला है जिसमें किसी मंत्री की संलिप्तता का खुलासा हुआ है और देश की सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लेते हुए गंभीर टिप्पणी करते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों से नुकसान की भरपायी करने तथा राज्य के दोषी अधिकारियों के खिलाफ छह माह में अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है। उस हालत में जबकि देश में विकास के नाम पर, औद्योगिक कारखानों, एक्सप्रेस–वे या आल वैदर रोड के नाम पर या फिर पर्यटन के नाम पर पेड़ों को, जंगलों को विकास प्रक्रिया की भेंट चढ़ाना जारी है और इनके खिलाफ जनता द्वारा किये जा रहे धरने, विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन सब के सब बेमानी हो गये हैं।अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का परिणाम भविष्य में क्या होगा। यदि यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो देश एक दिन हरित संपदाविहीन भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन की दशा में वन्य जीव संरक्षण के दावे बेमानी हो जायेंगे। पेड़ों के बिना लोग ऑक्सीजन के अभाव में अकाल मौत के मुंह में जाने को विवश होंगे। कोरोना काल के भयावह मंजर से भी यदि देश के नीति–नियंताओं ने सबक नहीं सीखा, तो उस दशा में क्या होगा, यह किसी से छिपा भी नहीं है।

चुनावी बांड स्कीम से आहत हुआ वोटतंत्र

चंदा देने वाले नहीं चाहते कि उनके दान देने के बारे में दूसरी पार्टी को पता चले। इससे उनके प्रति दूसरी पार्टी की नाराजगी नहीं बढ़ेगी।विपक्ष ज्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी ? मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामें मे कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार नही है कि पैसा कहाँ से आया अटॅार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार नहीं है वकीलों ने कहा कि ये बॉन्ड केवल रिश्वत हैं, जो सरकारी फैसलों को प्रभावित करते हैं।

पंकज कुमार मिश्रा, मिडिया विश्लेषक एवं पत्रकार जौनपुर यूपी

वरिष्ठ और महंगे वकीलों की श्रेणी में शुमार कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड पर प्रतिबंध के फैसले के बाद इस जजमेंट पर कहा कि लोकतांत्रिक चुनाव के दृष्टिकोण से विगत 25 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह सबसे बड़ा न्याय संगत फैसला है तो क्या महोदय यह कहना चाह रहें की अब तक के फैसले अन्याय और पक्षपात पूर्ण थे.! बतौर सोशल मिडिया कोर्ट नें मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार ऐसा फैसला सुनाने का साहस किया है जो कि केंद्र सरकार से सीधे जुड़े होने के साथ ही यह भारत की जनता के अधिकार एवं पूंजीपतियों, राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता बनाये रखने को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। अब बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को यह जानकारी देनी होगी कि 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने– कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे ! ऐसे में काले धन को सफ़ेद करने वाले पक्षऔर विपक्ष के बड़े बड़े बिज़नसमैन परेशानी में पड़ सकते है। एसबीआई तीन हफ्ते में यह जानकारी देगी। उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक यह जानकारी पहुंचाएगा। अब आइए जानते है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या ? कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था और ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आम चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता था। चीफ जस्टिस ने कहा, 'पॉलिटिकल प्रॉसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं।पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी, वह प्रक्रिया है, जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। मुख्य न्यायधिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने तीन दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस याचिका के याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कांग्रेस नेता जया ठाकुर शामिल रहीं। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, एवं विजय हंसारिया ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है। देगा। इसके जरिए ब्लैकमनी को व्हाइट करना संभव होगा।

15 मार्च को रिलीज होगी विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी'

सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित फिल्म 'बस्तर ॱ द नक्सल स्टोरी' 15 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेत्री अदा शर्मा की मुख्य भूमिका है। मेकर्स ने 'बस्तर ॱ द नक्सल स्टोरी' के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर में अदा शर्मा को अपने बेजोड़ अंदाज में देखा जा सकता है। आशिन ए शाह द्वारा सह–निर्मित इस फिल्म के ट्रेलर में नक्सलियों द्वारा 'सीआरपीएफ' जवानों को मारने की दिल दहला देने वाली झलक है, इसके अलावा इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अलगाववादियों के द्वारा देश के जवानों की मौत का जश्न मनाया जाता है। इंसानों को काटने के सीन से लेकर राष्ट्रगान गाने पर बच्चों को जलाए जाने, राजनीतिक हस्तियों की गोली मारकर हत्या करने और निर्दोष लोगों को फांसी पर लटकाए जाने के सीन्स तक ने इस ट्रेलर को जबरदस्त बना दिया है। सिने दर्शकों को लुभाने वाले सभी एलिमेंट से भरपूर यह फिल्म उन्हें एंटरटेन करने की क्षमता रखती है। 'द केरल स्टोरी' की जबरदस्त सफलता के बाद, वही टीम एक और डेयरिंग और प्रभावशाली विषय के साथ वापस लौटी है, जिसका ट्रेलर सभी के उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है।

प्रस्तुति: काली दास पाण्डेय

महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार मिला

गोंदिया। वैश्विक स्तरपर फ्रांस मेरा शरीर मेरा अधिकार नारे के साथ महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश जरूर बन गया है, परंतु महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार और सुरक्षित वैधानिक रूप से मान्य सेवाओं तक गर्भपात सीमित करने का नियम विनियम व कानून बनाने के सुझाव को भी रेखांकित करना जरूरी है।क्योंकि यदि इस संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग कर जांच में बेटी पाए जाने पर गर्भपात करवाया जाता है,तो फ्रांस के लिए भविष्य में महिला–पुरुष संतुलन में भारी विपत्ति से गुजरना पड़ सकता है। इसका सटीक उदाहरण हमें आज भारत में अनेक समाजों में बड़ी उम्र के लड़कों का वैवाहिक संबंध नहीं जुड़ने और कुंवारे बैठे रहने से संलग्न करके देखना होगा। बता दें कि भारत में हालांकि अभी महिला पुरुष संतुलन ठीक है, परंतु अगर हम तीन दशक पहले की बात करें तो 1994–96 में एक ऐसा दौर चला था जब स्त्रीलिंग का परीक्षण कर भारी मात्रा में अबॉर्शन यानी गर्भपात हुए थे, जिससे रेखांकित कर उस समय की सरकार ने बहुत सक्ति बरती और सख्त कानून बना दिए थे। परंतु उसका दुष्टपरिणाम हम आज देख रहे हैं कि उस अवधि की उम्र की महिलाओं की कमी के कारण भारी मात्रा में लड़के कुंवारे बैठे हैं, उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही है, यह समस्या अनेकों समाजों में व्याप्त है जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर अपनी राइस सिटी गोंदिया में भी पाया के अनेक लड़के 30–40 उम्र पार कुंवारे बैठे हैं,उन्हें विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। चुंकि फ्रांस में दिनांक 5 फरवरी 2024 को महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देकर इतिहास रचा गया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया है, परंतु इसकी आलोचनाएं भी हो रही है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार के दुष्टपरिणाम को रोकना जरूरी है। सुरक्षित वह वैधानिक रूप से मान्य सेवाओं तक गर्भपात सीमित हो इसे रेखांकित करना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम फ्रांस में महिलाओं को गर्भपात का संविधानिक अधिकार प्राप्त होने की करें तो,फ्रांस की संसद ने एक बड़े विधेयक को मंजूरी दी है। फ्रांसीसी संसद ने सोमवार को गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए मतदान किया। मतदान में इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी गई है। इस मतदान के पक्ष में 780 वोट पड़े, वहीं इसके विरोध में सिर्फ 72 वोट ही पड़े। मतदान के बाद फ्रांस अपने मूल कानून में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करने वाला दुनियां का पहला देश बन गया। वहीं इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद गर्भपात कराना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई और इस कदम की सराहना की। बता दें कि संसद के दोनों सदन नेशनल असेंबली और सीनेट पहले ही फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं, ताकि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी दी जा सके।

साथियों बात अगर हम फ्रांस में गर्भपात संबंधी कानून और फिर संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने की यात्रा की करें तो फ्रांस में गर्भपात को लेकर 1975 में एक कानून लाया गया था। तब फ्रांस में गर्भपात को कानूनी अधिकार दिया गया था। अब इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वहीं वेटिकन समेत गर्भपात विरोधी समूहों ने इस बदलाव की कड़ी आलोचना की है।फ्रांस की संसद के निचले सदन में स्पीकर संयुक्त सत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि फ्रांस यह कदम उठाने वाला पहला देश है। स्पीकर ने कहा कि उन्हें गर्व है कि महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है। विधेयक पारित होने से पहले फ्रांसीसी पीएम ने कहा कि हम सभी महिलाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि वे अपने बारे में खुद निर्णय ले सकती हैं। फ्रांस की सरकार महिला दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी और इस फैसले का जश्न मनाएगी। राष्?ट्रपति ने कहा कि उन्?होंने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया था। अब उनका ये वादा पूरा हो गया है। बता दें कि फ्रांस में 1974 के कानून के बाद से महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार प्राप्त है।जिसकी उस समय आलोचना की थी लेकिन महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले रोए बनाम बाड़े के फैसले को पलटने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद पूरी दुनिया की नजरें फ्रांस में इस कदम पर थी।

साथियों बात अगर हम फ्रांस में मेरा शरीर मेरा अधिकार नारे की करें तो इस फैसले पर लोगों ने एफिल टावर पर इकट्ठा होकर मेरा शरीर, मेरा अधिकार के नारे लगाते हुए अपना समर्थन जताया। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले संसोधन पर वोटिंग से पहले फ्रांस केपीएम ने संसद में कहा कि गर्भपात का अधिकार खतरे में था और निर्णय लेने वालों की दया पर निर्भर था। मॉडर्न फ्रांस के डॉक्यूमेंट में 2008 के बाद से ये 25वां संसोधन है। पीएम ने कहा कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि आपके शरीर परआपका ही अधिकार है और कोई दूसरा इसे लेकर फैसला नहीं कर सकता है। संसद में इस संसोधन का विरोध कर रहे नेताओं ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर सियासी फायदे के लिए संविधान का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आलोचकों का कहना है कि यह संविधान संसोधन अपने आप में गलत है और गैर–जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति इसके जरिए वामपंथी विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं।फ्रांस के संविधान में ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब 2022 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है।अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब अलग–अलग राज्य अपने स्तर पर गर्भपात को रोकने के लिए बैन लगा सकते हैं। इस फैसले से लाखों महिलाओं के गर्भपात के अधिकार खत्म हो गए हैं।साथियों बात अगर हम भारत में गर्भ का चिकित्सीयसमापन (संशोधन) अधिनियम 2021 की करें तो,राज्यसभा ने गर्भ का चिकित?सकीय समापनअधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित?सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी।इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएंॱ विशेष श्रेणी की महिलाओं, जिनके बारे में एमटीपी नियमों में किये जाने वाले संशोधनों में परिभाषित किया जाएगा, के लिए गर्भ काल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करना और इसके दायरे में बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार और अन्य कमजोर महिलाओं (जैसे दिव्यांगमहिलाओं,नाबालिग)आदि को शामिलकियाजायेगागर्भधारण के 20 सप्ताह तक के गर्भकी समाप्तिकेलिए एक प्रदाता (चिकित्सक)की राय और गर्भधारण के 20–24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए दो प्रदाताओं (चिकित्सकों) की राय की जरूरत होगी।मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान के क्रम में बताए गए हैं।

किशन सनमुख़दास भावनानी

अपनी समस्या हमें बतायें

आपके साथ या आपके आस–पास कोई घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, जुर्म हुआ है या उत्पीड़न हुआ है अथवा आपके क्षेत्र की समस्या है और आपकी समस्या जायज है तो आपकी समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं शासन–प्रशासन तक पहुंचाने के लिये बी पी एस न्यूज आपके साथ है। आपकी खबर शत् प्रतिशत प्रकाशित की जायेगी। एवं आपका नाम व नम्बर आपके अनुसार प्रकाशित या पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा।
दिये गये नम्बर पर काल करें या हमें ई मेल करें।

फोन नं.- 8423454502, bps.knp786@gmail.com

आवश्यक सूचना

प्रिय ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि बी.पी.एस. न्यूज समाचार पत्र में नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। कृपया चेक/डी.डी. बी पी एस न्यूज के नाम से ही चेक आदि भेजें। नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। नगद भुगतान करने पर विज्ञापनदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे। - सम्पादक

आवश्यकता है

बी पी एस न्यूज राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक, साप्ताहिक समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) के लिये समस्त तहसीलों एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरो चीफ, संवाददाताओं, छायाकार तथा विज्ञापन प्रतिनिधियों युवक–युवतियों की आवश्यकता है।
सम्पर्क करें -:
मो.: 8423454502
email:bps.knp786@gmail.com

बूथों पर पढ़ी गई वोटर लिस्ट, डीएम ने देखी हकीकत

बीपीएस न्यूज

कानपुर ।भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 23 जनवरी 2024 को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जा चुका है। जिसके क्रम में प्रकाशित वोटर लिस्ट को 9 मार्च तथा 10 मार्च 2024 को जनपद के समस्त मतदान केंद्रों में मतदाताओं की उपस्थिति में प्रकाशित वोटर लिस्ट को समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त उनके नामित बूथों पर मतदाताओं की उपस्थिति में वोटर लिस्ट को पढा जा रहा है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा आज डॉ वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक एजुकेशन सेंटर कैंट तथा कैलाश नाथ बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन का निरीक्षण करते हुए मतदाताओं की उपस्थिति में वोटर लिस्ट को पढा गया ।

निरीक्षण के दौरानजिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार जनपद कानपुर नगर के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। जिसके क्रम में उनके क्षेत्रांतर्गत समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को टैग करते हुए उन्हें सूचित करें कि वे अपनी स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अपने निवास स्थान से भी मतदान कर सकते है जिसके लिए उन्हें निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जिसके लिए समस्त बीएलओ को आगामी 5 दिनों में अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के समस्त मतदाताओं को उपलब्ध जानकारी देते हुए उनकी स्वेच्छानुसार फार्म-12डी भरवाने हेतु उन्हें अवगत कराए।

साथ ही मतदाता सूची में प्राप्त कर्मियों को संकलित कर यथाशीघ्र ठीक करना सुनिश्चित करें । तथा अपने क्षेत्र अंतर्गत समस्त दिव्यांग मतदाताओ को टैंग करते हुए उनकी भी सूची बनाना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि अपने विद्यालय में अध्ययन रत समस्त छात्र छात्राओं का निर्वाचन से पहले अलग-अलग कक्षाओ में माता-पिता की पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन कर उन्हें मतदान करने हेतु जागरूक करें तथा मतदान के बाद पुनः पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन करें जिसमें यह जानकारी प्राप्त करें कि उनके अभिभावक द्वारा मतदान किया गया कि नही।

संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला महिला का शव

मौके पर पहुंचा मायका पक्ष, किया हंगामा, लगाया हत्याकर फांसी के फंदे से लटकाने का आरोप

न्यू आजाद नगर चैकी क्षेत्र का मामला, पुलिस ने शुरू की जांच

बीपीएस न्यूज

कानपुर । कानपुर के न्यू आजाद नगर चैकी क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की देर दात एक महिला का शंव संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से झूलता मिला, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और मृतका के परिजनों को दी गयी। सूचना पाकर मृतका के ससुराल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा लोगों को शांत कराया गया। मायके पक्ष क्षरा महिला की हत्याकर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार थानाक्षेत्र सेन पक्ष्यिमपारा की न्यू आजाद नगर चैकी के जोगईपुरवा, गोपाल नगर निवासी अश्वनी यादव की 2019 में डेरापुर, कानपुर देहात के रहने वाले स्व0 राकेश कुमार की पुत्री दिव्या यादव से शादी हुई थी। दिव्या का शव रविवार देर रात उसके ही ससुराल में फांसी के फंदे से लटकते पाया गया। सूचना पाकर पुलिस और मायका पक्ष घटनास्थल पर पहुंच गया। मायके पक्ष के लोगों को हंगामा करते हुए ससुरालियों पर आरोप लगाया गया कि दिव्या की हत्याकर उसके शव को फंदे से लटका दिया गया है। मृतक दिव्या के भाई अर्पित का कहना है कि उसका बहनोई अश्वनी बेरोजगार था और शराबी था। शराब पीकर आयेदिन वह उसकी बहन के साथ मारपीट करता था और जबसे दिव्या के पुत्री हुई उसको प्रताडित करने का मामला भी बढता जा रहा है। बताया कि रविवार को उसकी बहन के साथ उसके बहनोई से मरपीट की थी, उसे छत पर ले गये थे, जिसकी जानकारी मृतका दित्या ने फोनकर अपने मायकेवालों को भी दी थी। मौके पर छत पर टूटे गमले भी मिले और उसी रात कुछ देर बाद उसकी मौत की सूचना आ गयी। पुलिस द्वारा मायके पक्ष कों शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू की गयी।

बेसिक शिक्षा : तबादले के लिए बढ़ा इंतजार

परीक्षा और चुनाव के कारण बेसिक शिक्षकों का ट्रांसफर अटका

बीपीएस न्यूज

लखनऊ/कानपुर। बेसिक शिक्षकों को अंतर्जनपदीय तबादलों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तबादलों की मांग को लेकर काफी संख्या में शिक्षक कोर्ट गए थे और उनको मार्च में तबादलों की उम्मीद थी लेकिन अभी परीक्षाएं होनी है और फिर लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में उनको तबादलों के लिए गर्मी की छुट्टी तक का इंतजार करना होगा। बेसिक शिक्षकों के अंत:जनपदीय और अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू हुई थी तब से लगातार तकनीकी दिक्कतों और कानूनी दांव-पेच में प्रक्रिया उलझती गई। अंत:जनपदीय तबादले तो जून 2023 में पूरे हो गए लेकिन अंतर्जनपदीय म्युचुअल तबादले लटके रहे। बाद में विकल्प मांगे गए और म्युचुअल तबादलों के लिए शिक्षकों ने जोड़े भी बनाए। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक मुकदमे का हवाला देकर प्रक्रिया रोक दी। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस मुकदमे का हवाला दिया गया है उसका इन म्युचुअल तबलादलों से कोई वास्ता नहीं है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं।

कैसे फंस गया मामला-

तबादला प्रक्रिया बार-बार अटकने के बाद शिक्षकों ने कई अधिकारियों से कई बार वार्ता की लेकिन जब बात नही बनी तो शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। हाई कोर्ट में पहले 13 शिक्षको ने याचिका दायर की। इसमें कोर्ट ने कहा है कि इनके तबादले सत्र के अंत में कर दिए जाएं। उसके बाद दो अलग-अलग समूहो में 53-53 शिक्षक और कोर्ट गए। अब और शिक्षक जाने की तैयारी कर रहे है। शिक्षको का कहना है कि कोर्ट ने सत्र के अंत में याचियों का तबादला करने को कहा है। सत्र मार्च में खत्म हो रहा है ऐसे में कोर्ट के निर्देशानुसार याचियों का अभी तबादला कर देना चाहिए पर अधिकारियों ने इस बारे में कोर्ट में यह हवाला दिया है कि मार्च में परीक्षाएं होनी हैं। अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें कई शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है और लोकसभा चुनाव भी हैं। चुनाव के बाद पारदर्शी प्रक्रिया से ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे।

इनामिया हिस्ट्रीशीटर और उसके गुर्गे की पैरवी करना पड़ा महंगा

कानपुर। कानपुर पुलिस ने इनामी आरोपियों की पैरवी करने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया है। ? पुलिस अधिकारी को फोन करके गिरफ्तारी न करने को कह रहा था। ? अपने आप को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय मंत्री बताता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक लाख के इनामी आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। जिसने पुलिस अधिकारियों पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तार न करने का दबाव भी बना रहा था। जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। ? मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। जो अपने आप को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री बताता है। घटना बर्रा थाना क्षेत्र की है।आलोक कुमार पुत्र दिनेश वर्मा निवासी जरौली थाना बर्रा ने तहरीर देकर अजय ठाकुर, अभय भदोरिया सहित 6 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अजय ठाकुर पर एक लाख व अन्य पर 25 हजार इनाम घोषित किया था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी।

पुलिस पर बना रहा था दबाव

कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार गजेंद्र सिंह राजावत पुत्र इंद्र बहादुर सिंह निवासी दीनदयाल पुरम बिनगवां थाना सेन पश्चिम पारा को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपियों को संरक्षण दे रहा था। अपने आप को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय मंत्री बताता है। सरेंडर न करने की सलाह दे रहा था। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों पर अनुचित दबाव बना रहा था।

लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बीपीएस न्यूज

कानपुर। एसएनसेन बीवी पीजी महाविधा में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार महिलओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

, जिसका शुभारंभ एसीपी पुलिस कमिश्नरेट पीसीएस सृष्टि सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिखा अधिकारी डा0 श्याम शंकर सिंह तथा प्रचार्या प्रो0 सुमन व सचिव पीके सेन द्वारा किया गया।

एसीपी सृष्टि सिंह ने लेंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 से सम्बन्धित सभी कानूनी धाराएं बताते हुए आश्वासन दिया कि आवश्यकता पडने पर वो हम सबके साथ है। उन्होने कार्यक्रम के सफल आयोजन कि लिए महाविधालय को बधाई दी और भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों हेतु शंभामनाये दी। प्रो0 सुमन ने महाविधालय के सुरक्षित वातावरण पर गर्व प्रकट किया व कहा कि आने वाले समय में महाविधालय में छात्राओं, शिक्षिकाओं तथा सभी के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय बढायेगे। डा0 रचना निगम के निर्देशन ने छात्राओं ने पोस्टर बनाकर एक्ट 2013 के विषय में जागरूकता का पदर्शन किया। कार्यक्रम में डा0 रेखा चैके ने कहा कि लैंगिक उत्पीडन केवल महिलाओं से नही, बल्कि पूरे समाज से जुडा हुआ मुददा है, संवेदनशीलता बढेगी तभी जागरूता बढेगी। इस दौरान प्रो0 अल्का टंडन, प्रो0 गार्गी यादव, डा0 अनामिका तथा अन्य शिक्षिकायें उपस्थित रहीं।

सोशल मीडिया के जरिये सटोरियों के चक्कर में फंसा था छात्र

कानपुर। कानपुर में काकादेव में ऑनलाइन सट्टे में रुपये हारने पर खुदकुशी करने वाला प्रतियोगी छात्र नवनीत इंस्टाग्राम के जरिये सटोरियों के चक्कर में फंसा और फिर उबर नहीं सका। दोस्तों से उधार लेने के साथ ही उसने अपने घर से अतिरिक्त खर्च लेना शुरू कर दिया था।शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता ने बिलखते बोले, अगर पता होता कि बेटा ऐसे भंवर में फंसा हुआ है, तो उसे अपने पास बुला लेते। काकादेव स्थित एक हॉस्टल में शुक्रवार शाम बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रुपमपुर गांव निवासी पूर्व प्रधान लालता प्रसाद शाक्य के बेटे नवनीत (19) ने फंदा लगाकर जान दे दी थी।लालता अपने बड़े बेटे निर्देश को दिल्ली में सिविल सर्विसेज व नवनीत को शहर में नीट की तैयारी करा रहे थे। काकादेव में नवनीत अपने हमउम्र चाचा संदीप के साथ हॉस्टल में रहता था। पिता ने बताया कि सप्ताह भर पहले नवनीत ने छह हजार रुपये मांगे थे, जो उन्होंने तीन दिन पहले बेटे के खाते में भेजे थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अग्निकांड से सुरक्षा की मॉक ड्रिल का आयोजन

बीपीएस न्यूज

कानपुर । जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, ए सी आई आयल्स प्रा लि, एग्रोटेक फूड्स प्राइवेट लि, एसीआई गारमेन्ट डिवीजन कानपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा प्रबंधन विषय पर एक प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल आयोजित की गई शिविर का शुभारम्भ डारेक्टर हर्ष अग्रवाल ने किया प्रशिक्षण लखन शुक्ला मुख्य प्रशिक्षक आपदा प्रबंधन ने दिया। लखन शुक्ला ने बताया ड्रिल के दौरान काल्पनिक फायर का वास्तविक फायर फाइटिंग किया गया। जिसमे कम्पनी की फायर सेफ्टी टीम रेस्कू टीम प्राथमिक उपचार टीम व साइड सेफ्टी टीम ने अपना प्रदर्शन किया लखन शुक्ल ने बताया कि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग मॉक ड्रिल के माध्यम से करते रहना चाहिए जिससे उपकरणों की क्रियाशीलता पता चलती है लखन शुक्ल ने बताया किसी घटना के तीन कारण लापरवाही अज्ञानता जल्दबाजी है। शुक्ल ने बताया आग ऑक्सीजन ईंधन तथा उचित ताप के मिलने पर ही लगती है। इन तीन तत्व में किसी एक को कम या हटा दे तो आग पर काबू पाया जा सकता है साफ सफाई का सुरक्षा से गहरा सम्बन्ध है जितनी बेहतर सफाई होगी हम उतना सुरक्षित होंगे आग को बुझाने की दृस्टि से 5 भागो में बाटा गया है ए- लकड़ी कोयला कागज यानि ठोस पदार्थो की आग बी- तरल पदार्थो की आग सी -गैस की आग डी-,धातुओ की आग ई- बिजली की आग के बारे में बताते हुए फायर सिलेंडर के उपयोग की विधि का भी डैमो दिया साथ ही घायल अवस्था में पट्टी बांधने से खून बहने पर रोकने के तरीके बताए, सीपीआर और घायलों के ट्रांसपोर्टेशन का भी डेमो दिया इस अवसर पर हर्ष वर्धन अग्रवाल यश वर्धन अग्रवाल, विमल जैन आशीष कुमार मिश्रा, बी पी त्रिपाठी सोरभ कुमार, वीके सिंह अनुज साहू सुनील प्लांट के कर्मचारी सुरक्षा कर्मी आदि उपस्थित रहे।

बलात्कार से पीड़ित युवती काट रही थानों के चक्कर

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कानपुर के थाना बिधनू क्षेत्र में एक युवती का बलात्कार हो जाता है। घटना के दौरान वह अपने भाई के साथ ट्रक में उन्नाव जाने का सफर कर रही थी। सफर के बीच खेतों में भाई के शौच जाने के बाद पीडित के गांव का निवासी ट्रक चालक ने क्लीनर के साथ मिलकर युवती का बलात्कार किया और फिर भाई तथा बहन को जान की धमकी देते हुए उन्नाव में ट्रक से उतार दिया। पीडित युवती तथा उसका भाई पहले अपने निवास स्थान वाले थाने पहुंची जहां से दोनो को बिधनू थाने भेज दिया गया। अब दोनो भाई-बहन थानो के चक्कर लगा रहे है।

जानकारी के अनुसार हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय युवती बीती 24 फरवरी को अपने भाई के साथ उन्नाव जा रही थी। पीडिता की माने तो उसके पिता दिव्यांग है तथा पति और उनकी माता उन्नाव के एक ईट भटठे में रहकर मजदूरी करती है और वह दोनो भाई बहन उन्ही के पास जा रहे थे। पीडिता ने बताया कि वह अपने भाई के साथ गांव से निकली थी और गांव के ही रहने वाले ट्रक चालक पिंटू के ट्रक में बैठ गऐ। बताया कि बिधून शंभुआ ओवरबिज के पास उसका भाई ट्रक से उतरकर खेतों में जब शौच के लिए गया हुआ था, तब चालक पिंटू और क्लीनर से जबरन उसके साथ ट्रक के केबिन में बलात्कार किया और उसके तथा भाई के विरोध करने पर उन्हे जान से मारने की धमकी दी गयी। बताया कि उसके बाद उन्हे उन्नाव में उतार कर वह लोग लखनऊ की ओर चले गये। पीडिता ने घटना अपने माता-पिता को बताई। पीडिता, मां और भाई के साथ वह कुरारा थाना पहुंची जहां मामला बिधनू थाने के बताकर उन्हे बिधनू भेज दिया गया, कई चक्कर लगाने के बाद पीडित परिवार पुलिस अधिकारी से मिला, जिसके उपरान्त थाना बिधनू में पुलिस ने मुकदा दर्ज कर पीडिता को मेडिकल के लिए भेज दिया वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने ज्ञापन दिया

बीपीएस न्यूज

कानपुर। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने मांगों को लेकर मंडल संयोजक इंजीनियर ए एन द्विवेदी के नेतृत्व में ज्ञापन जिलाधिकारी को सोपा! ज्ञापन के दौरान कहा कि प्रदेश पेंशनर्स की निम्नलिखित समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति सहित प्रदेश के विभिन्न पेंशन संगठनों द्वारा सक्षम स्तर पर निरंतर भ्रष्टाचार एवं विचार विमर्श के माध्यम से प्रयास किया जा चुका है ।

परंतु किसी भी समस्या के समाधान की दिशा में कोई सकारात्मक आदेश निर्गत नहीं

हुए आगे कहा की प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक आयोजन 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ, 70 व 75 वर्ष की आयु पर कर्मचारी 5त्न 10त्न का 15त्न की पेंशन वृद्धि, सेवानिवृत्ति के समय राशि कृति धनराशि की 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष में बहाली , केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन बहाली का लाभ दिया जाए! इंजीनियर ए एन द्विवेदी, विनोद कुमार दीक्षित राम जी श्रीवास्तव उषा देवी केपी सिंह प्रताप नारायण सचान सुरेंद्र तिवारी लोग मौजूद रहे!

हर रविवार संचालित होगी आनंद विहार टर्मिनल-पुरी एक्सप्रेस

कानपुर । रेलवे द्वारा नई ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से दिलली तथा ओडिशा के जगन्नाथ धाम जाने वालो को काफी सुविधा हो जायेगी। यह नई ट्रेन आज से कानपुर सेंट्रल से हर सप्ताह संचालित की जायेगी रेलवे जनसंपर्क अधिकारी रागिनी सिंह ने बताया कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन के रास्ते दिल्ली और ओडिशा के जाने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया गया। उन्होने बताया कि ट्रेन संख्या 18427-18428 पुरी-आनंद विहार टर्मिनल-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन 9 मार्च से शुरू कर दिया गया है तो वहीं ट्रेन संख्या 18428 आनंद विहार टर्मिनल-पुरी एक्सप्रेस अब हर रविवार को 10 मार्च से संचालित की जायेगी, जिसका ठहराव सेंट्रल स्टेशन पर भी होगा।

भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक से दिव्यांग बोर्ड में हुई अभद्रता, दिव्यांगो में रोष

राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने घटना की कड़े शब्दों में की निन्दा

दिव्यांग बोर्ड से आर0के0 सिंह को न हटाया गया तो होगा आन्दोलन

बीपीएस न्यूज

कानपुर। दिव्यांग बोर्ड के बड़े बाबू द्वारा दिव्यांग बोर्ड मे दिव्यांगजनो से अभद्रता करने व अपमानित करने कि घटना आय दिन बढ़ती जा रही है। अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तर क्षेत्र के संयोजक हिरदेश सिंह के साथ दिव्यांग बोर्ड के बड़े बाबू आर0 के0 सिंह ने ने उर्सला अस्पताल में लगने वाले दिव्यांग बोर्ड में उस समय अभद्रता किया जब वो 15 दिव्यांगजनो का प्रमाण पत्र बनवाने गये थे। हिरदेश सिंह ने इस घटना कि शिकायत जिलाधिकारी व पार्टी के जिला अध्यक्ष से किया है। उन्होंने कहा है कि आर0के0सिंह को दिव्यांग बोर्ड से नहीं हटाया गया तो भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर धरना देगी। उधर जैसे ही इस घटना कि जानकारी राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार को हुई तो उन्होंने इस घटना कि निन्दा की और कहा कि दिव्यांगजनो का अपमान बरदास्त नहीं किया जायेगा। जल्द ही इस मामले में दोषी वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो होने वाले आन्दोलन मे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी अपनी सहभागिता दर्ज करायेगी।

उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर किया वितरण

बीपीएस न्यूज

कानपुर। गोविंद नगर विधानसभा अंतर्गत विधायक सुरेंद्र मैथानी के द्वारा जमुई गांव पनकी में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर वितरण किया गया।उक्त वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में माता बहनों एवं गांव वालों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मोदी जी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना से माता बहनों को, गैस के निशुल्क कनेक्शन के वितरण के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घर-घर वितरण कराकर पात्रता के आधार पर लाभार्थियों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार संभव हुआ है। विकसित भारत की गाड़ी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है उसके माध्यम से सरकार जनता के द्वार,लगातार जा रही है और यदि किन्हीं कारणों से यदि कोई लाभार्थी छूट रहा है तो उसको तुरंत मोदी एवं योगी की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराया जा रहा है। उदय ने कहा कि आप लाभार्थी लोग भी अन्य पात्रता के आधार पर छूटे लोगों को बताएं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में रजिस्ट्रेशन करवा ले और आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड के लिए भी तथा सरकार की योजनाओं से वंचित लोग भी लाभार्थी बने। योजनाओं का लाभ उठाएं।क्योंकि यह पहली बार, आम जनता ने देखा कि, कैसे उनके दरवाजे पर आकर,सरकार उनको लाभ पहुंचा रही है।जमुई गांव में वितरण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी एवं प्रशांत पाल तथा बृजेंद्र सिंह एवं विवेक ठाकुर तथा सौरभ सिंह एवं कुलदीप सिंह तथा ज्योति दुबे, सरोज सिंह, गरिमा सिंह, मुन्नी श्रीवास्तव,माया देवी,रीता सिंह,सिलारा देवी,राखी सिंह, श्याम प्यारे, राजकीय सिंह आदि लोग मौजूद रहे!

घर के बाहर टहल रही महिलाओं से शराबियों ने की अभद्रता, विरोध करने पर की मार-पीट

शराबियों के खिलाफ थाना पनकी में दी गयी तहरीर

बीपीएस न्यूज

कानपुर। दो महिलाओं को देर रात्रि भोजन के बाहर टहना भारी पड गया। पडोस के ही कुछ शराबियों ने पहले तो महिलाओं पर गंदी फब्तियां कसी और अभद्र भाष का प्रयोग किया और जब महिलाओं द्वारा इसका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गयी। शोरगुल सुनकर घर से बाहर निकले एक महिला के पति को भी शराबियों ने पीट दिया। घटना के बाद पीडित परिवार सहम गया और उसके द्वारा थाना पनकी में शराबियों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।जानकारी के अनुसार थाना पनकी क्षेत्र के शताब्दी नगर में कल की बीती देर रात कुछ शराबियों ने दो महिलाओं पर कमेंट कर दिया। बताया जाता है कि महिलाऐ खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रही थी और उनके ही पडोस में रहने वाले कुछ युवक जो गाडी में बैठकर शराब पी रहे थे उन्होने बदत्तमीजी की। पीडित महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी और साली घर के बाहर टहल रही थी और अपने मोबईल से सेल्फी ले रही थी कि तभी कार सवार शराबियों ने कुछ फब्तियां कसी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बताया कि पत्नी तथा साली के विरोध करने पर मारपीटी की और जब वह घर के बाहर निकले तो उन्हे भी पीटा गया। किसी प्रकार घर में घुसकर सभी ने अपनी जान बचाई। डरे-सहमे परिजनों ने घटना के बाद थाना पनकी में तहरीर दी। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाई शुरू की गयी। पीडिता ने बताया कि शराबियों ने इतना होने के बाद उनके घर पर पत्थर भी फेंके जिससे उनकी खिडकियों के शीशे टूट गये साथ ही दरवाजा भी तोडने की कोशिश की। पुलिस द्वारा दोनो शराबी युवकों को हिरासत में लेकर पूंछतांछ करते हुए जेल भेज दिया गया।

मार्ग दुर्घटना में चालक व परिचालक गंभीर रूप से हुए घायल

आगे चल रहे डंफर ने मारी अचानक ब्रेक, पीछे से घुसा ट्रक

कानपुर नगर, कल की बीती देर रात घाटमपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके कारण उस ट्रक के पीछे चल रहा एक डफंर ट्रक में घुस गया तो वहीं उसके पीछे दूसरा डंफर भी टकरा गया। हादसे में पीछे वाले डंफर के चालक तथा परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गये।

जानकारी के अनुसार घाटमपुर क्षेत्र के पतारा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक ब्रेक लग दी, जिससे उसके पीछे चल रहे दो डंफर पीछे से ट्रक से भिड गये। इस हादसे में पीछे चल रहे ट्रक का चालक तथा परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गये। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनो घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भिजवाया जहां हालत गंभीर होने के कारण दोनो घायलों को हैलट भेज दिया गया। बताया जाता है कि हादता पतारा के टेनापुर मोड के पास हुआ तथा इसमें दिव्यांश तथा अखिलेश जो हमीरपुर के रहने वाले है वह बुरी तरह जख्मी हो गये है।

अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन

बीपीएस न्यूज

कानपुर । राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत डीडीएमए कानपुर नगर तथा नोबेल एकेडमी फायर सेफ्टी इंजीयरिंग द्वारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लि0, मयूर ग्रुप के कार्यालय में अग्नि सुरक्षा आपदा प्रबंधन विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ प्रशिक्षक लखन शुक्ला किया गया।

कार्यशला में लखन शुक्ला ने बताया कि ड्रिल के दौरान काल्पनिक केमिकल फायर की वास्तविक आग का वास्तिविक फायर फाइटिंग किया गया। बताया कि सरुक्षा उपकरणों का प्रयोग मॉक ड्रिल के माध्यम से करते रहना चाहिए, जिससे उपकरणों की क्रिया शीलता पता चली है। किसी घटना के तीन कारण लापरवाही, अज्ञानता तथा जल्दबाजी है। आग ऑक्सीजन ईधन तथा उचित ताप के मिलने पर ही लगती है। इन तीन तत्व में किसी एक को कम या हटा दे तो आग पर काबू पाया जा सकता है। उन्होने भूकंप, आकाशीय बिजली से बचाव के तरीके भी बताऐ। इस अवसर पर जीएम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लि0द्व डजीएम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी, कर्मचारी रहे। ट्रेनिंग के समय प्रबंध निदेशक मनोज गुप्ता, मनोज शर्मा, मृदुलेन्द्र सिंह, प्रवेश तिवारी, राजीव श्रीवास्तव, यस मेहता, एकेराव, अभिषेक मिश्रा, धर्मेन्द सिंह, आशुतोष शुक्ला तथा प्लांट के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

दो दोस्तों के आपस के प्रेम की कहानी, बदला लेने पहुंचा था कानपुर युवक

नही भायीं दोस्त की बेवफाई, इंदौर से कानपुर पहुंचे युवक ने लगाई कार में आग

कानपुर। कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते है, जिनपर विश्वास नही होता। आधुनिकता चाहे जितनी भी हो लेकिन भारत देश जैसे स्थान पर ऐसे विषयों पर न सोच आगे बढती है और नही ही समाज भी। इसके बावजूद भी हम हमारे बीच शायद समय के साथ बदलाव शुरू हो चुके है और ऐसे दृश्य हमे भविष्य की ओर कुछ खास संकेत देते दर्शायी देते है। एक ऐसे ही रोचक घटना सामने आई जिसमें एक लडके ने अपने लडके दोस्त द्वारा शादी से मनाकर देने में आक्रोशित हो उठा और वह भी इतना की इंदौर से सीधा कानपुर पहुंचा और अपने पुरूष मित्र की कार में आग लगा दी। इस घटना को अंजाम देकर वह भाग निकला लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया।हुआ कुछ यूं कि श्याम नगर निवासी अनूप कुमार शुक्ला के पुत्र वैभव शुक्ला की मित्रता इंदौर पीएफ कॉलोनी, जंजीबाग थाना साउथ तुकोगंज इंदौर, एमपी निवासी दीप तनवानिया से थी। दोनो का ही रिश्ता दोस्ती से ऊपर उठ चुका था और वैभव ने दीप से शादी का वादा इस शर्त पर कर लिया की उसे अपना लिंग परिवर्तन कराना होगा। दीप भी राजी हो गया। बताया जाता है कि दीप ने लगभग 50 से 60 लाख रूपये खर्च कर अपना जेंडर चेंज कराया था और लडकियों जैसा दिखने के लिए उसने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी तथा फेस सर्जरी भी कराई थी।

जेंडर बदलने, ब्रेस्ट सर्जरी तथा फेस सर्जरी कराने तक की क्रिया में दीप ने लगभग एक करोड रूपये खर्च कर दिया था और अब वह लडकियों जैसा दिखने लगा था।

उसने सोचा था कि वैभव अब उससे शादी कर लेगा, पर ऐसा हुआ नही। वैभव शादी से मुकर गया और कहा कि शादी तो हो जायेगी, लेकिन तुमसे बच्चे नही हो सकते है और वैभव ने शादी से मना कर दिया। मायूस और आक्रोशित दीप हबीबगंज भोपाल निवासी अपने दोस्त रोहन के साथ कानपुर पहुंचा और दोनो ने एक किराए की स्कूटी ली, रविार की रात वह वैभव शुक्ला के घर पहुंचा और उसकी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

कैसे पकडा गया दीप व उसका साथी रोहन

बस शादी के लिए अपने खास दोस्त से मिले इस धोखे के बाद दीप का गुस्सा इतना ही निकला की वह वैभव के घर पहुंचा और उसकी कार में आग लगा दी। इसके बाद वह मौके से भाग निकला। वहीं वैभव के पिता अनूप शुक्ला ने बताया कि उनकी कार पार्किंग में खडी थी और जल रही थी। उन्होने अग्निशमन यंत्र से किसी प्रकार कार में लगी आग को बुझाया और जब घर का सीसी टीवी फुटेज चेक किया तो पाया कि दो युवको ने उनकी कार में आग लगाई है। इसी सूचना उन्होने चकेरी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की खोज शुरू की और आरोपियों को कानपुर से 40 किलोमीटर दूर अरेस्ट कर लिया। पूंछतांछ के बाद दोनो आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आयुक्त मोबाईल कोर्ट में 28 दिव्यांगों की रखी समस्याएं

बीपीएस न्यूज

कानपुर। दिव्यांगजन आयुक्त उत्तर प्रदेश के कोर्ट में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने 28 दिव्यांगजनो की समस्या प्रस्तुत करवाया। जिस पर आयुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया।

वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि परियोजना अधिकारी डूडा, पुलिस आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसील, आयुध निर्माणी से जुड़े मामले उन्होने उठाया । डूडा कार्यालय ने दिव्यांगजनो का आसरा आवास योजना में आरक्षण नहीं दिया है, वही तहसील मे दिव्यांगजन के आय प्रमाण पत्र आमदनी से अधिक के बनाये जा रहे है, पुलिस द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजनो कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है , मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में यू0 डी0 आई0 डी0 कार्ड आफ लाईन दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नही बनाया जा रहा है, दिव्यांगजन का अक्षमता प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, वही आयुध निर्माणी में पारिवारिक पेंशन के लिये परेसान करने की शिकायत दर्ज कराई।वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि मोबाईल कोर्ट से दिव्यांगजनो की समस्याओं का त्वरित समाधान होने से दिव्यांगजन में आशा कि किरण जगी है7 समय समय पर मोबाईल कोर्ट का आयोजन होना चाहिए।

शूटिंग क्या है?

ओलंपिक 2024 में
भारत की आस

स्पोर्ट्स शूटिंग में फायरआर्म (बंदूक) का इस्तेमाल करके बुलेट को एक लक्ष्य पर निशाना लगाना होता है। ये स्थिर लक्ष्य या गतिशील लक्ष्य हो सकते हैं जिन्हें क्ले नाम से जाना जाता है।

शूटिंग के प्रकार

राइफल

- **50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन** में पुरुषों को 40 राउंड फायरिंग, महिलाओं को 20 राउंड।
- **50 मीटर राइफल प्रोन** में लेटकर 60 शॉट।

50 मीटर लांग राइफल

- **10 मीटर एयर राइफल** में खड़े होकर पुरुषों को 60 राउंड, महिलाओं को 40 राउंड।

10 मीटर एयर राइफल

पिस्टल

- **50 मीटर** में पुरुषों के लिए **60+20 राउंड** गोली।
- **25 मीटर रैपिड फायर** में लड़कियों के लिए **30 गोलियां**।
- **25 मीटर रैपिड फायर** में पांच टारगेट पर डिफरेंट टाइम के बीच फायर।

10 मीटर एयर पिस्टल

- **25 मीटर सेंटर फायर** में पुरुषों के लिए **दो राउंड में 60 गोलियां**।
- **25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल** में पुरुषों के लिए 3 राउंड में अलग-अलग समय में **20 राउंड फायर**।
- **10 मीटर एयर पिस्टल** में पुरुषों को 60 राउंड, महिलाओं को 40 राउंड।

25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल

शॉटगन

12 गेज शॉटगन

- **ट्रैप- शूटर** को टारगेट पर बंदूक सीधी रखकर गोली चलानी होती हैं।
- **डबल ट्रैप** में **दो बर्ड** (नकली) पर निशाना लगाना होता है।
- **स्कीट** में दो अलग-अलग दिशाओं से बर्ड उड़ता है जिसे शूट करना होता है।

ओलंपिक में कब शामिल हुआ शूटिंग?

1896 के ओलंपिक उद्घाटन में 5 इवेंट से लेकर आज 6 डिसिप्लीन में 15 इवेंट तक ये खेल फायरआर्म टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ तेजी से बढ़ा है।
2008 ओलंपिक्स में **अभिनव बिंद्रा** ने शूटिंग में **गोल्ड** जीतकर देश का मान बढ़ाया था।

2024 पेरिस ओलंपिक में भारत को आस

भारत को 10 मीटर एयर राइफल में **सरबजोत सिंह** से,
10 मीटर पुरुषों की एयर राइफल में **अर्जुन बबूता** और

महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में **त्रिलोतमा सेन** से मेडल की आस है।
25 मीटर पिस्टल में **मनु भाकर** से, **अनीस भानवाला** से

पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, महिलाओं की 50 मीटर राइफल में **श्रीयंका साडंगी** से मेडल की आस है।

अब सैफई के नाम से डर नहीं लगता : सीएम

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 बेड अस्पताल का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को आज 12:10 पर सैफई पहुंचे। जहां वह सैफई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम के मंच पर पहुंचे तो तालियां बजाकर उनका लोगों ने स्वागत किया। कुलपति प्रोफेसर/डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पताल की उपलब्धियां बताई।

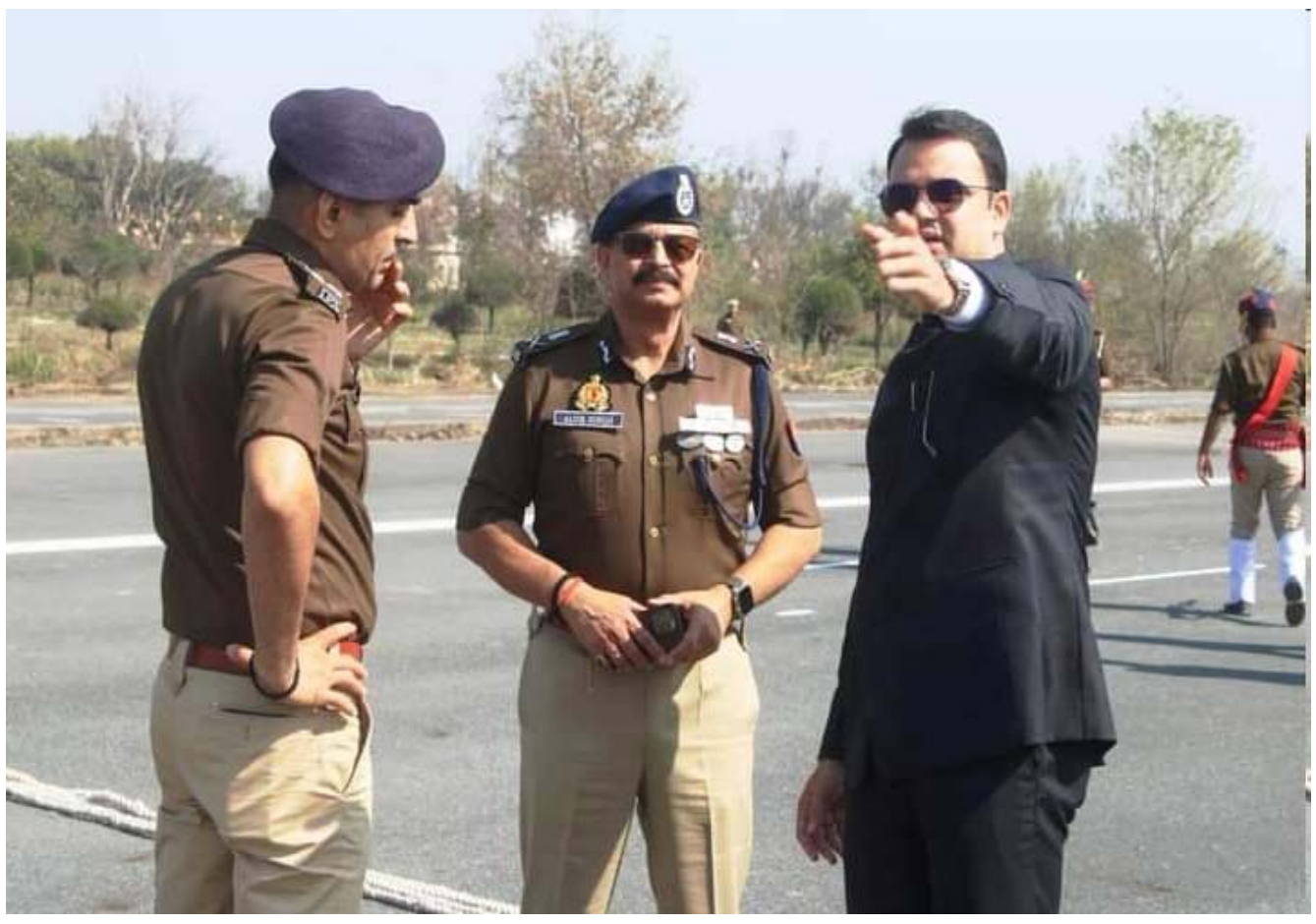

सीएम की सुरक्षा में अलर्ट पर रहे अधिकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इटावा के सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे । इस दौरान एडीजी कानपुर ज़ोन आलोक सिंह व डीआईजी कानपुर रेंज जोगेन्द्र कुमार द्वारा कार्यक्रम स्थल,हेलीपैड,यातायात-रूट व्यवस्था व अन्य सम्भावित स्थलों की सुरक्षा-व्यवस्था का निरीक्षण कर ड्यूटी पर लगे समस्त अधिकारी व कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए थे।

बीपीएस न्यूज

इटावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को आज 12:10 पर सैफई पहुंचे। जहां वह सैफई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम के मंच पर पहुंचे तो तालियां बजाकर उनका लोगों ने स्वागत किया। कुलपति प्रोफेसर/डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पताल की उपलब्धियां बताई। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चिकित्सा राज्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, सांसद राम शंकर कठेरिया, विधायक सरिता भदौरिया मौजूद हैं। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को सैफई में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए याद किया। उन्होंने कहा कि उनके इस विश्विद्यालय को बनवाने की वजह से पूरे भारत के छात्र यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इटावा के नाम से लोग डरते थे। अब यहां देश के युवा तैयार हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की कानाफूसी करने की आदत रही है। अब सबके लिए काम होता है। मोदी जी के सबका विकास के उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपचार के लिए रुपये की कमी नहीं। 108 और 102 के रिस्पॉन्स टाइम को काम किया है। हर जनपद में एडवांस लाइफ सपोर्ट की चार से पांच गाड़ियां हैं। जहां पहले पूरे प्रदेश में छह-सात कार्डिक की गाड़ियां थीं। अब सभी जनपद में हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार नारियल फोड़कर शुभारंभ तो कर देते थे, लेकिन बजट नहीं देते थे। मेडिकल कॉलेज को टोकन मनी के नाम पर एक लाख रुपये दिए जाते थे।सपा का बिना नाम लिए तंज कसा कि आज नियुक्ति पत्र पाने वालों के चहरे पर शिकन नहीं थी। अब इटावा और सैफई के नाम से डर नहीं लगता। 1996 का जिक्र करते हुए कहा कि वह जयपुर से आगरा रात में पहुंचे थे। वहां से कानपुर जाने के लिए पुलिस वालों ने मना कर दिया कि रात में न जाएं, इटावा पड़ेगा। अब ऐसा डर नहीं है।

योगी कैबिनेट का विस्तार, फिर पकड़ा ओपी राजभर ने सीएम योगी का हाथ, 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ

एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी के एक विधायक और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आज आगरा दौरे से लौटने के बाद यह विस्तार हो सकता है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के प्रमुख ओपी राजभर, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के अनिल कुमार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो सदस्य- दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा शामिल हैं।

ओपी राजभर ने कहा, गरीबों की सेवा का जो लक्ष्य है उसमें हम अनवरत काम करते रहते हैंज् सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे हम गरीब और कमजोर लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। ऋष्ठ विधायक अनिल कुमार ने कहा, मेरे लिए यह बहुत खुशी का पल है। मैं पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूंज्लोकसभा चुनाव में सब मजबूती से लड़ेंगे। भाजपा नेता दारा सिंह चौहान ने कहा, आज जो जिम्मेदारी मिली है उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगाज्मैं इस क्षण के लिए पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं।5 साल बाद ओपी राजभर की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में एक बार फिर वापसी हुई है। वहीं, सुनील शर्मा ने 2017 और 2022 के चुनाव में गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट को रिकॉर्ड अंतर से जीता था। राष्ट्रीय लोक दल के साथ भाजपा का हाल में ही गठबंधन हुआ है। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से रालोद के विधायक हैं। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया गया है। चुनाव से पहले भाजपा छोड़ वह सपा में चले गए थे। फिर वह विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में वापस लौटे और घोसी सीट से उपचुनाव लड़ा। लेकिन हार गए। अब वह भाजपा से विधानपरिषद के सदस्य है।

ईडी ने महादेव सट्टा एप मामले में भोपाल से गिरीश तलरेजा को किया गिरफ्तार, रतनलाल जैन उर्फ़ अमन की तलाश जारी

स्वप्निल तिवारी

मध्यप्रदेश, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव सट्टा एप मामले में गिरीश तलरेजा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरीश को बीती रात उनके निवास से भोपाल में गिरफ्तार किया गया। गिरीश तलरेजा महादेव सट्टा एप के मुख्य प्रमोटर हैं। इसके साथ ही भोपाल के रतनलाल जैन की भी तलाश जारी है। इस मामले में गिरीश तलरेजा के साथ अन्य साथी भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। गिरीश तलरेजा को भी महादेव सट्टा एप का प्रमोटर बताया जा रहा है।

गिरीश तलरेजा को गिरफ्तार किया जाने के बाद ईडी ने रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, पत्थलगांव, सूरजपुर, और प्रतापपुर में छापा मारा। महादेव सट्टा एप के संबंध में रतनलाल जैन के अनेक अंतरराष्ट्रीय धंधे सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैन कई अरब देशों में अवैध धंधे कर रहे हैं और भारत से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। भोपाल ईडी की टीम ने गिरीश तलरेजा को गिरफ्तार किया है और उन्हें रायपुर ईडी को सौंपा गया है। इस मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया जारी है। यह सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सरकारें सख्त कदम उठाएं।

इससे सामाजिक न्याय स्थापित होगा और अपराधियों को सजा मिलेगी। अब जांच की जा रही है कि कितने और लोग इस मामले में शामिल हैं और कैसे इसे समाधान किया जा सकता है। इससे पहले भी महादेव सट्टा एप के संबंध में कई मामले सामने आए हैं।

माली सैनी महासभा का कार्यक्रम आयोजित

माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर खिचड़ी वितरण किया गया

बीपीएस न्यूज

कानपुर। माली सैनी महासभा यूपी के संरक्षक महंत राम अवतार सैनी ,छेदीलाल सैनी , के प्रसाद सैनी, प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद सैनी ,प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पू सैनी, प्रदेश महामंत्री दिलीप कुमार सैनी, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज सैनी, मीडिया प्रभारी सीएल सैनी, मैरिज ज़्यूरो प्रभारी रोहित सैनी, सह प्रभारी गौरी शंकर सैनी, फूल मंडी ठेकेदार व संगठन मंत्री शिव कुमार सैनी , प्रचार मंत्री अरविंद सैनी , दीपक सैनी , आशीष सैनी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे । इस सभा के संयोजक फूल मंडी ठेकेदार शिवकुमार सैनी रहे। माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर खिचड़ी वितरण व कार्यक्रम की सर्वोज़म व्यवस्था के लिए संयोजक जी, बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

इंद्रलोक में 'नमाज' से जुड़ी घटना के बाद पुलिस, अर्ध्यसैन्य बल के जवान तैनात

नयी दिल्ली। इंद्रलोक में 'नमाज' पढ़ रहे लोगों को धक्का देने तथा 'लात' मारने की घटना के लिए दिल्ली पुलिस के एक उपनिरीक्षक को निलंबित किए जाने के एक दिन बाद इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अधिकारियों ने बताया कि अर्द्धसैन्य बलों की कम से कम तीन टुकड़ियों के साथ ही स्थानीय पुलिस शनिवार को उत्तरी दिल्ली में इंद्रलोक और उसके आसपास के इलाकों में तैनात रहेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इलाके में शांति कायम करने के लिए एक शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठकें भी कीं। संयुक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर) परमादित्य ने शनिवार को बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इलाके में शांति है। परमादित्य ने बताया, ''हमारे अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और इलाके में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं।'' उपनिरीक्षक मनोज कुमार तोमर ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली में एक सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को कथित तौर पर धक्का दिया और 'लात' मारी जिसके बाद सैकड़ों स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोपी पुलिसकर्मी को तुरंत निलंबित कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होने के बाद नेताओं समेत समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने इस कृत्य की निंदा की ।तोमर इंद्रलोक पुलिस चौकी के प्रभारी थे जो सराय रोहिल्ला पुलिस थाने के तहत आती है। उन्हें दो महीने पहले ही पुलिस चौकी में तैनात किया गया था। यह घटना इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के समीप दोपहर करीब दो बजे शुक्रवार की नमाज के दौरान हुई। कथित वीडियो में तोमर मस्जिद के नजदीक सड़क पर नमाज अदा कर रहे लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश करते और अचानक आक्रोशित होकर कुछ नमाजियों को धक्का देते व लात मारते दिखायी दे रहे हैं। घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क अवरुद्ध कर दी थी। यह घटना रमजान शुरू होने से कुछ दिन पहले हुई है।

बेंगलुरुः कार, बाइक सहित कोई भी वाहन धोया तो लगेगा 5000 रूपए का जुर्माना

कर्नाटक की राजधानी और भारत के आईटी हब बेंगलुरू में पानी का संकट गहराया हुआ है. इसी कारण शहर में गैर जरूरी इस्तेमाल से होने वाले पानी के नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. यहां व्हीकल्स (कार, बाइक, स्कूटर सहित अन्य) की धुलाई पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि व्हीकल की धुलाई में बहुत ज्यादा पानी खराब होता है. इतना ही नहीं, अथॉरिटी ने कई और चीजों के लिए पानी के इस्तेमाल पर बैन लगाया है.

बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने शहर में पानी के संकट के बीच व्हीकल्स की धुलाई, फव्वारे और बागवानी के लिए पानी के इस्तेमास पर रोक लगा दी है. इसका उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का ऐलान किया गया है. जारी आदेश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए पानी के इस्तेमाल, मनोरंजन के लिए बनाए गए फव्वारे, मॉल और सिनेमा हॉल में पीने के पानी के अलावा पानी के अन्य इस्तेमाल, सड़कों की सफाई और अन्य सफाई कामों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

बीडब्ल्यूएसएसबी के अध्यक्ष डॉ. राम वसंत मनोहर ने कहा, आदेश का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बार-बार उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और हर दिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा.

बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा है, शहर में तापमान बढ़ रहा है और बारिश की कमी के कारण भूजल स्तर नीचे चला गया है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वह पानी बर्बाद न करें और सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें.बीडब्ल्यूएसएसबी ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते दिखाई दे, तो बीडब्ल्यूएसएसबी के कॉल सेंटर पर शिकायत करें.

हाई कोर्ट से मिला बड़ा झटका, अब सीबीआई जांच के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को संदेशखली मामले में सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने वकील से रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष इसका उल्लेख करने को कहा। इससे पहले आज, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मामले के मुख्य आरोपी शाजहान शेख को सीबीआई को सौंपने का भी आदेश दिया ।पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बशीरहाट पुलिस से लेकर सीआईडी ??को सौंप दी थी, जो अब सीआईडी ??की पुलिस रिमांड में है। टीएमसी नेता को पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके एक दिन बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है ।बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल के संदेशखली से जबरन वसूली, भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न की कई शिकायतों के मुख्य आरोपी पूर्व तृणमूल नेता शेख शाहजहाँ की हिरासत सीबीआई को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने मंगलवार शाम कहा कि केंद्रीय एजेंसी मामले को अपने हाथ में लेगी, उन्होंने बंगाल पुलिस को शाहजहां और मामले की सामग्री सौंपने के लिए शाम 4.30 बजे तक का समय दिया था।

आवारा कुत्तों के बजाय मानव जीवन को दें प्राथमिकता, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में राय दी कि आवारा कुत्तों की तुलना में मनुष्य के जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आवारा कुत्तों को पालने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश, योजनाएं या नियम बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्ते प्रेमी जानवरों की रक्षा कर सकें।आवारा कुत्तों के हमले के डर से छात्र अकेले स्कूल जाने से डरते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कार्रवाई हुई तो कुत्ते प्रेमी विरोध करेंगे. आवारा कुत्तों का उत्पात दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अदालत ने कहा, कुत्ते प्रेमियों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि वास्तविक कुत्ते प्रेमियों को प्रिंट और विजुअल मीडिया में लिखने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जस्टिस पीवी कुंजीकृष्णन ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से चर्चा कर एक गाइडलाइन या योजना तैयार की जाए।

अदालत ने कन्नूर के मुज़हादम के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें राजीव कृष्णन नामक निवासी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो अपनी संपत्ति पर आवारा कुत्ते पाल रहा था। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि राजीव कृष्णन को एक महीने के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए और कन्नूर निगम को सख्त शर्तों के साथ कानून के तहत लाइनें जारी करनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि लाइसेंस आवेदन जमा नहीं किया गया है तो निगम को घर के परिसर से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल जुलाई में, केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में एक पक्ष के रूप में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था और शीर्ष अदालत को अवगत कराया था कि आयोग को आवारा कुत्तों के उपद्रव और बच्चों की दुर्दशा के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। जिन्हें उनके द्वारा घातक रूप से काटा गया है और आयोग ने ऐसी कई घटनाओं पर स्वत-संज्ञान लेकर मामला भी उठाया है।

चीन में मस्जिद बनाने से पहले लेनी होगी इजाजत, जिनपिंग सरकार का तुगलकिया फरमान

चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में धर्म के नाम पर चीनी सरकारी कड़ा एक?शन लेने वाली है. मुस्लिम-बहुल क्षेत्र में यह नियम सबसे सख?त होंगे. शिनजियांग में धर्म को नियंत्रित करने की चाहत में एक जबरदस?त प?लान बनाया गया है. इसका सीधा असर चीन में रहने वाले उइगर, कज़ाख, किर्गिज़ और हुई (उर्फ डुंगन्स) जैसे मुस्लिम जातीय समूहों पर पड़ेगा.

बिना अनुमति के नहीं बना पाएंगे मस्जिद

इस नियम के तहत चीन में कोई भी नई मस्जिदों, चर्चों और अन्य धार्मिक इमारतों को बनाने या उसे मरम?मत करने से पहले झिंजियांग के क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी. किसी भी धार्मिक आयोजन को करने या कराने से पहले कम से कम एक महीने पहले स्थानीय सरकार से इसकी भी अनुमति लेनी पड़ेगी. धर्म से जुड़ा कोई भी कंटेंट ऑनलाइन पोस?ट करने से पहले आप उसे रि०?यू कराएंगे. जिसे क्षेत्रीय सरकार की तरफ से जांचा जाएगा.

उधर मुस्लिमों पर सबसे अधिक बुरा असर

जानकारों का कहना है कि इसका सीधा असर उइगर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समूहों पर पड़ेगा. ऑक्सस सोसाइटी फॉर सेंट्रल एशियन अफेयर्स के प्रबंध निदेशक ब्रैडली जार्डिन ने बताया, 卐यह कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन के धर्मों को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और समुदायों से काटने और उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी में सामाजिक और राजनीतिक रूप से अलग-थलग रखने के बारे में है.

दस लाख मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जेल में कर दिया गया है बंद

चीन पर शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप हमेशा से लगता रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दस लाख से अधिक उइगर, कजाख और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पहले से डिटेन सेंटर और जेल में बंद कर रखा गया है. चीन इस मामले पर हमेशा चुप?पी साधे रखा है, लेकिन परेशान लोगों की गवाही और लीक हुए आधिकारिक चीनी सरकारी दस्तावेज के आधार पर इस तरह के मामले दुनिया के सामने आए हैं. जिसमें जबरन श्रम से लेकर यौन शोषण, जबरन नसबंदी और उइगर मुस्लिमों के सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मिटाना, मस्जिदों को तोड़ना और अन्य शामिल हैं.

चीन की जबरदस्ती, मुस्लिम देश चुप

इन कार्रवाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों और कई पश्चिमी सरकारों ने चीन पर नरसंहार के आरोप भी लगाए हैं. 2022 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया कि चीन शिनजियांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है जो मानवता के खिलाफ है. जब भी कोई देश या संस?था इन

मामलों को दुनिया के सामने या चीन के सामने उठाती है तो चीन इसे सरासर मना कर देता है. जबकि चीन इस मामले में बड़े सफाई से कहता है कि वह अपने देश में जो कुछ भी कर रहा है, उसमें किसी का भी मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा. वह तो अपने प्रांत शिनजियांग में उग्रवाद और आतंकवाद जैसे नीतियों का मुकाबला कर रहा है.

1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से कम्युनिस्ट सरकार की नास्तिक विचारधारा के कारण देश के अंदर धर्म को दबाने और नियंत्रित करने के लगातार प्रयास किए गए हैं.

मनमाने आदेशों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

सभी बीएसए का आज और कल प्रशिक्षण होगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है निर्देश

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने छह और सात मार्च को प्रदेश के सभी बीएसए का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने का आदेश जारी किया है। सचिव ने इसका आदेश याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की बीएसए की अक्षमता को लेकर की गई तल्ख टिप्पणी के बाद दिया है ।कोर्ट ने कहा था कि शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाध्यकारी उपबंधों और नियमों की अनदेखी कर मनमाने आदेश दे रहे हैं। ऐसे कई मामले कोर्ट में आए जिसमें बीएसए ने विभागीय जांच के उपबंधों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस की। मनमाना आदेश देने वाले बीएसए फर्रुखाबाद के खिलाफ कड़ा आदेश जारी करने के बजाय कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी। सचिव ने फौरन प्रदेश के सभी बीरसए को दो दिन के प्रशिक्षण में शामिल होने का आदेश जारी कर रिपोर्ट कोर्ट में दी। कोर्ट ने सचिव की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। साथ ही याची के संबंध में पारित बीएसए फर्रुखाबाद का आदेश रद्द करते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति याची को देकर छह हफ्ते में नियमानुसार जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

सभी विभागों को 15 मार्च तक बजट स्वीकृत करने के निर्देश

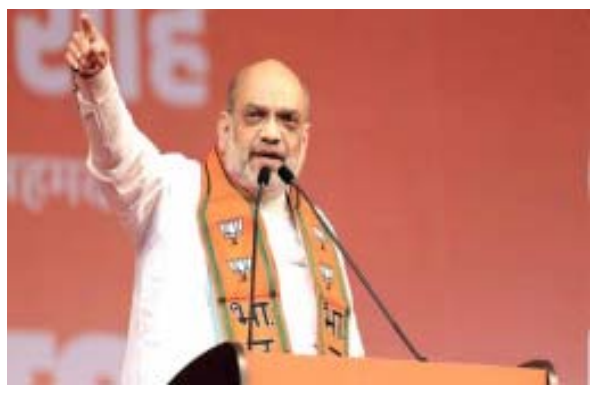

लखनऊ। शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 मार्च तक बजट स्वीकृतियां हर हाल में जारी कर दें। साथ ही ये भी तय किया जाए कि वित्तीय स्वीकृतियां उससे जुड़े अधिकारी तक अधिकतम 20 मार्च तक पहुंच जाएं। इस संबंध में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। कोषागारों द्वारा सभी भुगतान ई पेमेंट के जरिये किए जा रहे हैं। कोषागार किसी भी भुगतान के लिए चेक जारी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आनलाइन बिल प्रस्तुतिकरण, पीएफएमएस और ई कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 मार्च तक वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर ये भी तय कर लें कि 20 मार्च कक संबंधित आहरण अधिकारी तक पहुंच जाएं। सभी आहरण अधिकारी अधिकतम 25 मार्च तक कोषागार में बिल जमा कर दें।

सीएए कानून चुनाव से पहले होगा लागू, कोई नहीं रोक सकताः गृह मंत्री अमित शाह

देश में सीएए को लेकर जारी राजनीतिक तकरार के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कहा है कि सीएए इस देश का कानून है और यह चुनाव से पहले लागू होकर रहेगा। एक टीवी चैनल से बातचीत में शाह ने कहा कि सीएए देश का कानून है, पत्थर पर खींची लकीर है। ये वास्तविकता है कि ये लागू होगा और इस चुनाव से पहले लागू होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सीएए कानून कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस वोटबैंक के लालच में कई चीजें भूल गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1947 में बांग्लादेश से आये लोगों को नागरिकता देने का वादा किया था। फिर भी, वे लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।

शाह ने साफ तौर पर कहा कि ये लोग अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, महिलाएं बिना सुरक्षा के रह रही हैं और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है़अगर भारत उन्हें नागरिकता नहीं देगा, तो और कौन देगा? भारत उन लोगों का स्वागत करता है। हम उन्हें उनका हक दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यूसीसी संविधान सभा का वादा था। उन्होंने कहा कि अगर आज 15 अगस्त, 1947 में किये गए अपने वादे को पूरा नहीं करता तो ये ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 3 साल के अंदर अर्थात मोदी जी के तीसरे टर्म में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा।

भाजपा नेता ने कहा कि आज देश भर में प्रचंड जन समर्थन नरेन्द्र मोदी जी को, भाजपा को, ह्रछ को मिल रहा है। मैं देश के कोने-कोने में गया हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने-कोने से नरेन्द्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ओछी बातें करके देश की राजनीति के स्तर को गिराने का काम जो लोग कर रहे हैं, हर बार उन्हें जनता उसका जवाब दे रही है। मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, बहुत समय से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक मायने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। क्योंकि जिनका परिवार होता है, वो बेटे-बेटियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है। लेकिन मोदी जी ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है ।शाह ने कहा कि लोकतंत्र में हर चीज का जवाब जनता देती है, जनता सब देखती है। बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपये मिलते हैं, झारखंड में 355 करोड़ रुपये कैश मिलते हैं और ये कहते हैं कि हम पर एक्शन मत लो। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्कसरकार के खिलाफ 40 केस क्कको ही रजिस्टर करने पड़े थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर के अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए एजेंसियों का हौवा खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि 23 साल से नरेन्द्र मोदी जी सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से केंद्र में हमारी सरकार है। लेकिन 4 आने का भी आरोप मोदी जी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शिता से शासन किया है।

अखिलेश ने बसपा से गठबंधन होने की किसी भी संभावना से किया इनकार

लखनऊ। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बसपा के साथ गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि अब तो समय जा चुका है। लोकसभा चुनाव में समय नहीं बचा है। शायद 15 तारीख से पहले ही चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी, ऐसे में इस सबके लिए समय नहीं है।

अगले लोकसभा चुनाव में सोचा जाएगा कि उनसे गठबंधन करना है या नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती को साथ लाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता, जिससे किसी दल को नाराजगी हो। लेकिन सुनने में आता है कि उनके प्रत्याशी वही होते हैं, जिससे बीजेपी को लाभ मिले।

बसपा ने तेलंगाना में बीआरएस से किया गठबंधन

बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस (बीआरएस) के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने हैदराबाद में बीआरएस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मंगलवार को मुलाकात के बाद गठबंधन करने का घोषणा की। बता दें कि इससे पहले बसपा ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा था। जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती की सहमति से दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा।

निषाद पार्टी ने मांगी एक और लोकसभा सीट

निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने भाजपा से गठबंधन में एक और लोकसभा सीट की मांग की है। उन्होंने भाजपा से हारी हुई सीटों में एक सीट की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें यदि हारी हुई एक सीट मिलती है तो वह उसे जीतकर एनडीए को मजबूत करेंगे। इसके अलावा निषाद ने विधान परिषद चुनाव में भी एक सीट की मांग की है। मालूम रहे कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को भाजपा ने संतकबीरनगर से प्रत्याशी घोषित किया है।

कानपुर प्रेस क्लब द्वारा

पत्रकार व उनके परिवार का कराया गया निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

जांच के साथ उपचार भी कराया गया निशुल्क

अरुण कुमार अस्थाना (बीपीएस न्यूज)

कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, हैलट पीजीआई जीटी रोड, कानपुर मे पत्रकार और उनके परिवारों के लिए कानपुर प्रेस क्लब व जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जांच के साथ हर मर्ज का निशुल्क उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया।कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेई ने बताया कि कानपुर प्रेस क्लब व जीएसवीएम के द्वारा पत्रकार और उनके परिवार के लिए निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है।जिसके अंतर्गत फुल बॉडी चैकअप किया जा रहा है। अगर जांच में कोई बीमारी निकलती है, तो उसका जीएसवीएम द्वारा निशुल्क उपचार किया जाएगा। जेसीपी हरिश्चंद्र, डॉक्टर संजय काला (प्राचार्य), डॉक्टर आरके सिंह सीएमएस ने हेल्थ चेकअप शिविर का उद्घाटन किया।

हेल्थ कैंप को लेकर पत्रकारों में उत्साह देखने को मिला। पत्रकार साथी परिवार से मां, भाई, पिता, पत्नी, बहनों को लेकर स्वास्थ्य शिविर में आए और निशुल्क जांचें करवाई।

सभी पत्रकार साथियों का मानना है कि इलाज के लिए जो सुविधाएं हैलट के डॉक्टरों से मिल सकती है, वो बाहर कहीं नहीं मिल सकती है। लेकिन एक स्टेटस सिंबल के कारण लोग नर्सिंग होम की तरफ भाग रहे हैं। आज जो लोग पीजीआई परिसर में आए हैं, उनकी अवधारणा बदली है। और यह तय किया गया है, कि इसको लेकर पत्रकारों द्वारा समाज में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कि अगर किसी को कोई भी बीमारी होती है तो आप यहां पर एक बार जरूर आए और इलाज करायें। आपको कम पैसे में यहां अच्छा इलाज मिलेगा।

वही डॉक्टर अनिमेष द्वारा पत्रकार व उनके परिवार की जांच ओपीडी की गई। डॉक्टर महेंद्र सिंह (एच ओ डी) के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम द्वारा पैथोलॉजी में पत्रकारों का जांच परीक्षण किया गया। ई सी जी की जांच ईसीजी टेक्निशियन डॉ आशीष अवस्थी व डॉ राजेश कुमार कनौजिया द्वारा किया गया। डॉक्टर अर्पित सिंह रेडियो जे आर टू, डॉ शिवम् कुमार गौतम, डॉ मुरलीधरन, डॉ रजनीकांत द्वारा पत्रकारों का अल्ट्रासाउंड किया गया।

महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों ने की पूजा अर्चना

कानपुर। ब्राह्मण जागरूकता समिति के तत्वाधान में इस वर्ष महाशिवरात्रि के उपलक्ष में जय बाबा जलेश्वर धाम मंदिर में बाबा भोलेनाथ का सिंगार किया गया और उसके बाद बाबा का भोग ठंडाई से लगाकर सभी भक्तजनों को प्रसाद रूपी ठंडाई बांटी गई कार्यक्रम में मुख्य रूप से समिति अध्यक्ष अभय दुबे विपिन मिश्रा दीपक साहू आशुतोष गुप्ता संध्या दुबे महर्षि मिश्रा आशीष त्रिपाठी सोनी पूजा इत्यादि लोग रहे।वही महादेवन मंदिर के बाहर लगी थी भक्तों की लंबी लाइन। लोग दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लाइन में लगे हुए लोग बम बम के नारे भी लगा रहे थे। मंदिर के अंदर श्रद्धालु शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे। महादेवन मंदिर में अशोक शर्मा एवं उनकी पत्नी रेखा शर्मा ने बाबा का श्रृंगार किया, साथ ही भक्तों को प्रसाद के साथ-साथ खजाने का वितरण भी कराया।

अपराधी विनोद को न्यायालय ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा

लाख का अर्थ दंड ना जमा करने पर मिली 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा

कानपुर। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर व पुलिस उपयुक्त दक्षिण कानपुर नगर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त बाबूपुरवा के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु. अ. सं. 30/17 धारा 21/ 22 एन डी पी एस एक्ट के अभियुक्त विनोद पुत्र स्वर्गीय मुन्ना निवासी 133/136 कैनल पट्टी थाना जूही के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के फल स्वरुप अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय से समन्वय स्थापित कर विचारण सुनवाई पूर्ण करने के उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए का अर्थ दंड न जमा करने पर 1 साल का साधारण अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

कानपुर के तीन युवक अयोध्या की सरयू नदी में समाए

बीपीएस न्यूज

एक श्रद्धालु के बचाने में हुई तीनो युवकों की मौत

अयोध्या/कानपुर। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के संत तुलसीदास घाट पर रविवार को स्नान के दौरान श्रद्धालुओं का एक दल हादसे का शिकार हो गया। एक श्रद्धालु को बचाने के चक्कर में तीन की डूबकर मौत हुई है। हालांकि इनके तीन साथी सकुशल बच गए हैं। हादसे की जानकारी पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच कार्रवाई में जुटे हैं।कानपुर नगर जिले के बर्रा थाना क्षेत्र के वर्ल्ड बैंक कॉलोनी निवासी युवकों का एक दल रविवार को रामलला के दर्शन-पूजन के लिए अयोध्या आया था। दल में शामिल सभी युवक संत तुलसीदास घाट पर सरयू में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान सरयू का जलस्तर कम होने के चलते एक युवक गहरे पानी मे चला गया और डूबने लगा। साथियों ने उसको भरसक बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता न मिली। सूचना पर नयाघाट पर तैनात जल पुलिस के जवान और स्थानीय नाविक मौके पर पहुंचे लेकिन हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। अयोध्या कोतवाल मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि हादसे में रवि मिश्रा (20), प्रांशु सिंह चौहान (18) व हर्षित अवस्थी (18) की मौत हुई है। जल पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिया है, जबकि इनके साथियों कृष्णा सहगल, तनिष्क पाल व अमन शर्मा को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम आदि की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सूचना मृतकों के परिजनों को भिजवाई गई है। वहीं हादसे की खबर घर पहुंची तो हड़कंप मच गया है।

बी पी एस न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक
मुद्रक प्रकाशक स्वात्वाधिकारी बुद्ध प्रकाश साहू द्वारा मां प्रिन्टर्स गार्डेन नं. 6-ए/7 रेल बाजार कानपुर नगर से मुद्रित एवं 344- बगाही भट्ठा टी.पी. नगर कानपुर से प्रकाशित। आर.एन.आई. नं. UPHIN/ 2016/ 66740, डाक पंजीयन सं. कानपुर सिटी 304/2024-2026, सम्पादक बुद्ध प्रकाश साहू मो.: 8423454502, व्हाट्सअप 9335908846 email:bps.knp786@gmail.com info@bpsnews.in www.bpsnews.in नोट-समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कानपुर नगर न्यायालय होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त लेखों एवं समाचारों की जिम्मेदारी लेखकों व संवाददाताओं की होगी। कृपया कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर भेजें।